



वेतन आयोग

प्रलिस के लयः

वेतन आयोग, महेगाई भत्ता (DA), अखलि भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, [मुद्रास्फीति](#)

मेन्स के लयः

वेतन आयोग: उद्देश्य, सफारशें, चुनौतियाँ

संदर्भ:

वेतन आयोग एक आवश्यक संस्थागत तंत्र है जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों को नरिधारति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है। देश की प्रशासनिक व्यवस्था के एक मुख्य घटक के रूप में आयोग समय-समय पर मौजूदा आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करता है तथा [सार्वजनिक कषेत्र](#) के कार्यबल के लयि उचित पारशिरमकि सुनश्चिति करने हेतु वेतनमान में उचित संशोधन की सफारशि करता है।

वेतन आयोग:

- वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापति एक नकिया है जो कर्मचारियों के वेतन ढाँचे में बदलाव की समीक्षा और सफारशि करता है।
- वेतन आयोग की संरचना वय्य वभिग (वति मंत्रालय) के अंतर्गत आती है।
- वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 वर्ष में कया जाता है और पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापति कया गया था। आज़ादी के बाद से कुल सात वेतन आयोगों का गठन कया गया है।
- वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में कया जाता है और पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापति कया गया था। आज़ादी के बाद से कुल सात वेतन आयोग का गठन कया गया है।
- नवीनतम वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में कया गया था और इसकी सफारशें वर्ष 2016 में लागू हुईं। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग की सफारशें के आधार पर वेतन मलिता है।
- सरकार के लयि वेतन आयोग की सफारशें को मानना अनविर्य नहीं है। सरकार सफारशें को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

वेतन आयोग की आवश्यकता:

- वेतन में संशोधन: वेतन आयोग समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभों का आकलन करता है। वेतन में संशोधन की सफारशि करते समय यह मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति, जीवन यापन की लागत एवं प्रचलति बाज़ार दरों जैसे वभिन्न कारकों पर वचार करता है।
 - ये संशोधन यह सुनश्चिति करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को बदलते आर्थिक परदृश्य के अनुरूप उचित और प्रतसिपर्द्धी वेतन मलि।
- सार्वजनिक वति पर प्रभाव: वेतन आयोग की सफारशें का सरकार के वतितीय वय्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रभावति होते हैं।
- अन्य कषेत्रों पर रपिल इफेक्ट: वेतन आयोग की सफारशें अकसर नज़ी कषेत्र और वभिन्न राज्य सरकारी संगठनों में वेतन संरचनाओं को प्रभावति करती हैं। कई राज्य सरकारें तथा नज़ी कंपनियों भी अपने स्वयं के वेतन ढाँचे को संशोधति करते समय केंद्रीय वेतन आयोग की सफारशें को संदर्भ बदि के रूप में उपयोग करती हैं।
- सामाजिक समानता: वेतन आयोग वेतन असमानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी संबोधति करता है। साथ ही यह सुनश्चिति करता है कि सरकारी कर्मचारियों को उचित एवं प्रतसिपर्द्धी वेतन मलि, यह समाज के वभिन्न वर्गों के बीच आय असमानताओं को कम करने में मदद करता है।
- भत्तों और सुवधियों की समीक्षा: मूल वेतन के अलावा वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को प्रदान कयि जाने वाले वभिन्न भत्तों जैसे-आवास भत्ता, चकितिसा लाभ और यात्रा भत्ता आदि की भी समीक्षा करता है तथा उनमें बदलाव की सफारशि करता है।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सफ़ारिशें:

न्यूनतम वेतन: अकरोयड फॉर्मूले के आधार पर सरकार से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित करने की सफ़ारिश की गई है।

नोट:

- अकरोयड फॉर्मूला आवश्यक वस्तुओं में मूल्य परिवर्तन पर विचार करता है जो जीवन-यापन की लागत को प्रभावित करता है।
- इस फॉर्मूले से कर्मचारियों के प्रदर्शन और मुद्रास्फीति दर दोनों के आधार पर वेतन वृद्धि निर्धारित की जा सकती है।
 - इस तरह कर्मचारियों को उनके काम के लिये उचित पुरस्कार दिया जाता है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन को समायोजित किया जाता है।
- अधिकतम वेतन: एपेक्स स्केल के लिये 2,25,000 रुपए प्रतिमाह और वर्तमान में समान वेतन स्तर पर कैबिनेट सचिव एवं अन्य हेतु 2,50,000 रुपए प्रतिमाह।
- नई वेतन संरचना: ग्रेड वेतन संरचना के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए और अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है तथा एक नया वेतन मैट्रिक्स डिज़ाइन किया गया है।
 - ग्रेड पे को वेतन मैट्रिक्स में शामिल कर दिया गया है। कर्मचारी की स्थिति, जो ग्रेड वेतन से निर्धारित होती थी, अब वेतन मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित होगी।
- नई पेंशन प्रणाली: आयोग को नई पेंशन प्रणाली (NPS) से संबंधित कई शकियतें प्राप्त हुई हैं। इसने NPS के कामकाज में सुधार के लिये कई सफ़ारिशें की हैं। इसने एक मज़बूत शकियत नविवरण तंत्र की स्थापना की भी सफ़ारिश की है।
- वार्षिक वेतन वृद्धि: वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3% पर बरकरार रखी गई है।
- महँगाई भत्ता (DA): महँगाई भत्ते (DA) की दर फलिहाल 7% वेतन आयोग की सफ़ारिश पर तय की जाती है।

महँगाई भत्ता (DA):

- महँगाई के प्रभाव को कम करने के लिये सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA का भुगतान करती है। सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन में नरितर वृद्धि की आवश्यक है ताकि उन्हें बढ़ती कीमतों से नपिटने में मदद मिल सके।
- चूँकि मुद्रास्फीति का प्रभाव कर्मचारी के कार्य क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है, इसलिये DA की गणना उसी के अनुसार की जाती है। इस प्रकार DA शहरी, अर्द्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न होता है।
- इसकी गणना पिछले 12 महीनों के अखलि भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है।

वेतन आयोग के समक्ष चुनौतियाँ:

- आर्थिक स्थितियाँ: आर्थिक उतार-चढ़ाव और अनशिचितताएँ वेतन वृद्धि के लिये धन आवंटित करने की सरकार की क्षमता को प्रभावित करती हैं। यदि अर्थव्यवस्था स्वस्थ दर से नहीं बढ़ रही है, तो यह महत्त्वपूर्ण वेतन संशोधनों को लागू करने के लिये उपलब्ध संसाधनों को सीमित कर सकती है।
- राजकोषीय बाधाएँ: सरकार को अपनी राजकोषीय ज़िम्मेदारियों को संतुलित करना होगा, जिसमें बजट घाटे का प्रबंधन और सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करना शामिल है। राजकोषीय स्थिरता से समझौता कियेबना सरकारी कर्मचारियों के लिये उच्च वेतन की मांग को पूरा करना समस्या उत्पन्न कर सकता है।
- मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत: उच्च मुद्रास्फीति दर और जीवन-यापन की बढ़ती लागत व्यक्तियों की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन उचित जीवन स्तर बनाए रखने के लिये पर्याप्त है यह सुनिश्चित करने हेतु वेतन आयोग को इन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- आय असमानताएँ: सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के बीच आय असमानताओं को संबोधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नषिपक्ष एवं उचित वेतन संरचना को बनाए रखते हुए वेतन वृद्धि की आवश्यकता को संतुलित करना एक जटिल कार्य है।
- विभिन्न क्षेत्रों की मांग: अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उचित वेतन और लाभ की आवश्यकताएँ होती हैं। वेतन आयोग को रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की विधि आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये।
- वैश्विक आर्थिक कारक: वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ भारत की आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण वेतन संशोधन लागू करने की सरकार की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ: वेतन आयोग को पेंशन संबंधी मुद्दों का भी समाधान करना चाहिये और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की सफ़ारिश करनी चाहिये।

नषिपक्ष

नषिपक्ष के तौर पर वेतन आयोग की सफ़ारिशें भारत के कार्यबल के लिये नषिपक्ष और अधिक समृद्ध भविष्य की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। वेतन असमानताओं को दूर करके एवं लोक सेवकों के समर्पण को देखते हुए हम एक मज़बूत और अधिक प्रेरित कार्यबल के लिये मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे अंततः पूरे देश को लाभ होगा।

